

प्रेषक,

डा० राकेश कुमार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,  
उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्,  
मूयर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून: दिनांक: 23 जनवरी, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-2009 में सीमैट हेतु नियुक्ति कार्मिकों का वेतन आदि मदों में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1820/सीमैट बजट/2008-09, दिनांक 10.11.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु उत्तरांचल राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) हेतु नियुक्ति कार्मिकों के वेतन, भत्ते आदि पर व्यय हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में रु० 6,72,000/- (रुपये छः लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निर्वर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आयोजनागत पक्ष की धनराशि बचनबद्ध मदों यथा वेतन, मंहगाई भत्ता आदि एवं अवचनबद्ध मदों की प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि बी०एम०-13 पर अद्यतन व्यय विवरण उपलब्ध कराने पर ही वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त हो जायेगी।

- (2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- (3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।
- (4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्याधिव्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।
- (5) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों की विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- (6) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें। उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
- (7) अवशेष धनराशि की जिलावार फॉट एवं अनुदान संबंधी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जायें, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृत निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-02-माध्यमिक शिक्षा-101 के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुरंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-659/वित्त अनुभाग-3/2008, दिनांक 19.01.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डा० राकेश कुमार)  
सचिव।

✓ संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से)।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ०पी०तिवारी)  
उपसचिव।



शासनादेश संख्या-03/XXIV (1)/2009-11/2006, दिनांक 23 जनवरी,  
2009 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-11

(धनराशि हजार रुपये में)

लेखाशीर्षक		आयोजनागत
2202-	सामान्य शिक्षा	
02-	माध्यमिक शिक्षा	
004-	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	
03-	सीमेंट की स्थापना	
	01-वेतन	480
	03-मंहगाई भत्ता	77
	04-यात्रा भत्ता	5
	05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	10
	06-अन्य भत्ते	99
	20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1
कुल योग:-		672

(रुपये छः लाख बहत्तर हजार मात्र)

(ओपीओतिवारी)  
उपसचिव।